

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 33/2023

No. E.368/0/ACP/Pt.IV

Kolkata, Dated: 17/02/2023

All Concerned

(as per standard list)

**Sub: Grant of financial upgradation under MACPS by counting 50%
Temporary Status of Casual Labour Service and 100%
Temporary Status Service of Substitutes.**

A copy of Ministry of Railway (Railway Board) letter bearing no. PC-V/2021/MACP/23/NCR(E), dated 14/02/2023 (RBE No. 31/2023) on the above cited subject is circulated for information and further necessary action. Board's earlier letters dated 04/12/2009 (RBE No. 215/2009), 25/02/2010 (RBE No. 36/2010), 04/02/2020 (RBE No. 16/2020) and 30/04/2021 (RBE No.33/2021) mentioned therein were circulated under this office serial nos. 199/2009, 35/2010, 16/2020 and 34/2021 respectively.

DA: As above.


(Dharmendra Weekey)
Dy. Chief Personnel Officer/HQ
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone No. 24106(Rly.)
17.2.2023

Index No. 1060: Extant instructions regarding grant of financial upgradation under MACPS by counting 50% Temporary Status of Casual Labour Service and 100% Temporary Status Service of Substitutes stand withdrawn. Cases already decided need not be re-opened.

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No. PC-VII/ 203
No. PC-V/2021/MACP/23/NCR(E)

RBE No. 31/2023
New Delhi, dated 14-02-2023

The General Managers (P), All
Indian Railways and PUs.

Sub:- Grant of financial upgradation under MACPS by counting 50%
Temporary Status of Casual Labour Service and 100% Temporary
Status Service of Substitutes.

On receipt of references from some of the Zonal Railways regarding counting or otherwise of 50% Temporary Status Casual Labour Service and 100% Temporary Status Service of Substitutes for the purpose of MACP, the matter has since been examined in consultation with DoP&T. Pointing out Para 3 of their OM No. DoP&T's OM No. 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10-2019 (circulated vide Board's letter dated 04.02.2020/ RBE No. 16/2020) which stipulates that casual employees, including those granted 'temporary status' and employees appointed in the Government on ad-hoc or on contract basis, shall not qualify for the benefit under the Scheme, and Para 9 of Annexure-I to the said OM which provides that 'regular service' for the purpose of MACPS shall commence from the date of joining of a post in direct entry grade on a regular basis either on direct recruitment basis or on absorption / re-employment basis. Service rendered on casual, ad hoc / contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into reckoning, DoP&T has reaffirmed its decision communicated vide Item No. 6 of their OM dated 05-04-2021(circulated vide Board's letter dated 30-04-2021 / RBE No. 33/2021) regarding not counting 50 % of temporary status casual service for the purpose of MACPS. In light of DoP&T's above clarification the instructions issued vide Board's letter dated 04-12-2009/RBE No.215/2009 and Board's letter dated 25-02-2010/RBE No. 36/2010 stands withdrawn. However, the cases already decided need not be re-opened.

2. This has the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
3. Hindi version is enclosed.



(Sudha A. Kujur)
Deputy Director, Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

क्र.सं. पीसी-VIII/ 203

सं. पीसी-V/2021/एमएसीपी/23/एनसीआर(ई)

आरबीई सं. 31/2023

नई दिल्ली, दिनांक 14.02.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: नैमित्तिक श्रमिक की 50% अस्थायी सेवा और एवजियों की 100% अस्थायी सेवा की गणना करते हुए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना।

आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन से भी नैमित्तिक श्रमिक सेवा की 50% अस्थायी सेवा और एवजियों की 100% अस्थायी सेवा की गणना अथवा अन्यथा करने के संबंध में कुछ क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त होने पर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श पर इस मामले की जांच की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.10.2019 के का.जा. सं. 35034/3/2015-एस्टे. (डी) (बोर्ड के दिनांक 04.02.2020/आरबीई सं. 16/2020 के पत्र के तहत परिपत्रित) के पैरा 3 का उल्लेख करते हुए, जिसमें यह नियत है कि 'अस्थायी ओहदे' वाले कर्मचारियों सहित नैमित्तिक कर्मचारी और सरकार में तदर्थ अथवा ठेके के आधार पर नियुक्त कर्मचारी इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे तथा उक्त कार्यालय जापन के अनुबंध-1 के पैरा 9, जिसमें यह प्रावधान है कि आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए 'नियमित सेवा' की गणना सीधे भर्ती आधार अथवा समाहन/पुनर्नियुक्ति के आधार पर, नियमित आधार पर सीधे प्रवेश ग्रेड में पद ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी। नियुक्ति-पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति से पहले नैमित्तिक, तदर्थ/ठेके के आधार पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए अस्थायी ओहदे की नैमित्तिक सेवा की 50% की गणना नहीं करने के बारे में दिनांक 05-04-2021 के अपने कार्यालय जापन (बोर्ड के दिनांक 30-04-2021/आरबीई सं. 33/2021 के पत्र के तहत परिपत्रित) की मद सं.6 के तहत संसूचित अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में बोर्ड के दिनांक 04-12-2009/आरबीई सं.215/2009 के पत्र और बोर्ड के दिनांक 25-02-2010/आरबीई सं. 36/2010 के पत्र के तहत जारी अनुदेशों को वापस लिया जाता है। बहरहाल, जिन मामलों पर पहले से निर्णय लिया जा चुका है, उन्हें पुनः न खोला जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति प्राप्त है।



(सुधा ए.कुजूर)

उप निदेशक, वेतन आयोग

रेलवे बोर्ड